

INDEX

- Nine rapidly expanding glacial lakes found in himachal Pradesh
- बिहार में मार्च 2027 तक बनेगा हाईटेक इंडोर स्टेडियम
- जान टर्नस ने एप्पल के सीईओ का पद संभाला
- सरकार ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए 'वन टैग' सुविधा शुरू की है। इसके तहत वाहन मालिक FASTag का स्टिकर बदले बिना बैंक बदल सकते हैं। नया बैंक खाता उसी FASTag से डिजिटल रूप से जोड़ा जा सकेगा।
- 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स
- ESTIC 2026 क्या?
- मिशन रंगीन मछली 2031
- लक्षद्वीप का महत्व
- बुध ग्रह (Mercury) के सिकुड़ने की नई खोज
- US का PERM सिस्टम

Nine rapidly expanding glacial lakes found in Himachal Pradesh

SHIMLA, HIMACHAL PRADESH: The unprecedented devastation and loss of life in the wake of the Nepal flash floods have set off the alarm bells for Himachal Pradesh, with researchers from the Indian Institute of Technology (IIT) Mandi identifying nine rapidly expanding glacial lakes in the state — terming them ticking “water bombs”. These lakes could pose a serious threat to downstream communities as rising temperatures accelerate melting of glaciers across the Himalayas, IIT-Mandi researchers said.

The researchers, through analysis of satellite imagery and other datasets, found that the number of glacial lakes in the Himalayan region has increased by nearly 30% over the past decade — their size, too, has expanded significantly.

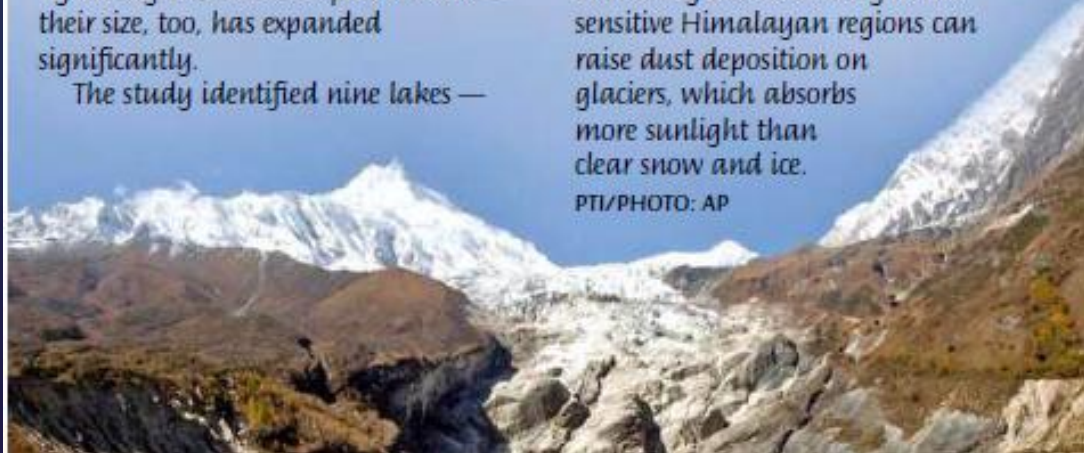
The study identified nine lakes —

Kalikund, Chandratal, Vasuki, Suraj, Kya Tso, Yoche, Samudra Tapu, Kasang and Gepang Gath — located in high-altitude regions of Chamba and Lahaul-Spiti as particularly vulnerable, capable of acting like “water bombs” if their natural barriers fail.

The study mapped 2,076 glacial lakes situated above 3,500 metres in Himachal Pradesh in 2025 and found that their cumulative area has increased by 28.45% over the past decade, underscoring the growing risk of glacial lake outburst floods (GLOFs) in the state.

The study also pointed out human activity as a possible factor accelerating glacier melt and cautioned that increasing tourist activity in the sensitive Himalayan regions can raise dust deposition on glaciers, which absorbs more sunlight than clear snow and ice.

PTI/PHOTO: AP



झील का नाम	सटीक लोकेशन (राज्य / जिला / क्षेत्र)	विशेष विवरण
1. कालिकुंडा (Kalikunda)	चमोली जिला, उत्तराखंड	यह उत्तराखंड के चमोली में कागभुशुंडी ताल (Kagbhusandi) के ट्रेक रूट के पास उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है।
2. चंदनताल / चंद्रताल (Chandantal)	लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	स्पीति घाटी में समुद्र तल से 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक प्रसिद्ध अर्धचंद्राकार झील है।
3. वासुकी ताल (Vasuki)	रुद्रप्रयाग जिला, उत्तराखंड	यह प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के ठीक ऊपर लगभग 4,135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र हिमानी झील है।
4. सूरज ताल (Suraj Tal)	लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	बारालाचा ला दर्रे (Baralacha La) के ठीक नीचे स्थित यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है।
5. क्या त्सो / क्यागर त्सो (Kya Tso)	लेह जिला, लद्दाख (या बारालाचा ला के पास, HP)	लद्दाख के रूपशू घाटी में (त्सो मोरीरी के रास्ते पर) तथा हिमाचल प्रदेश के बारालाचा ला दर्रे के पास स्थित उच्च पर्वतीय क्षेत्र।

6. योचे (Yoche)	लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	यह लाहौल घाटी के झास्कर या दारचा (Darcha) मार्ग पर स्थित एक छोटी लेकिन खूबसूरत हिमानी झील है।
7. चामुंडा तुपा (Chamunda Tupa)	लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	यह भी लाहौल क्षेत्र की ऊपरी दुर्गम चोटियों में स्थित एक कम ज्ञात हिमानी (Glacial) झील है।
8. कासांग (Kasang / Karang)	किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश	यह किन्नौर के कासांग नाला और कासांग जलप्रपात के ऊपरी ग्लेशियर क्षेत्र (कासांग घाटी) में स्थित है।
9. गेपांग गाथ / घेपन (Gepang Gath)	लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश	लाहौल घाटी के सिस्सू (Sissu) गांव के ठीक ऊपर स्थित एक बड़ी और तेजी से बढ़ती हिमानी झील है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण चर्चा में रहती है।



HIMACHAL PRADESH LAKES



Gadasru Lake

Mahakali Lake

Deepak Tal

Chamera Lake

Khajjiar Lake

Chandratal Lake

Sissu Lake

Manimahesh Lake

Lama Dal

Dashair Lake

Kareri Lake

Nag Dal Lake

Bhrighu Lake

Dehnasar Lake

Dhankar Lake

Nako Lake

Macchial Lake

Maharana Pratap Sagar

Parashar Lake

Pandoh Lake

Rewalsar Lake

Seruvalsar Lake

Gobind Sagar

Kamrunag Lake

Baraadsar Lake

Renuka Lake

Rani Tal



बिहार में मार्च 2027 तक बनेगा हाईटेक इंडोर स्टेडियम

बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंकड़बाग में ₹21.20 करोड़ की लागत से हाईटेक इंडोर स्टेडियम-II का निर्माण किया जा रहा है।

इसके मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- स्थान: पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कंकड़बाग, पटना
- परियोजना लागत: ₹21.20 करोड़
- पूरा होने का लक्ष्य: मार्च 2027
- प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के सीधे प्रसारण के लिए अलग प्रसारण कक्ष (Broadcasting Room) बनाया जाएगा।
- यह सुविधा खिलाड़ियों को 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक तथा प्रस्तावित 2030 राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) की तैयारी में सहायता करेगी।

जान टर्नस ने एपल के सीईओ का पद संभाला

न्यूयार्क, एपी: मशहूर टेक कंपनी एपल के नए सीईओ जान टर्नस ने एक सितंबर को कामकाज



संभाल लिया। इसके साथ ही टिम कुक का 15 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। इस

जान टर्नस • दौरान आइफोन की जबरदस्त लोकप्रियता की वजह से कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर 4.6 ट्रिलियन डालर हो गया।

नए सीईओ का आना एपल के लिए एक अहम मोड़ है। टर्नस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की दौड़ में एपल को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के तरीकों को खोजने के अलावा, उन्हें सप्लाय चैन से जुड़े सवाल और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के साथ रिश्तों को भी संभालना होगा। ट्रंप ने मंगलवार को उनके कुक की सार्वजनिक रूप से तारीफ की थी।



Tim Cook
becomes Apple Executive Chairman

FASTag का बैंक बदलना हुआ आसान, नितिन गडकरी ने शुरू की नई सुविधा; Rajmarg Yatra ऐप से होगा पूरा काम

सरकार ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए 'वन टैग' सुविधा शुरू की है। इसके तहत वाहन मालिक FASTag का स्टिकर बदले बिना बैंक बदल सकते हैं। नया बैंक खाता उसी FASTag से डिजिटल रूप से जोड़ा जा सकेगा।

◇ 'वन टैग' सुविधा क्या है?

- इसकी तुलना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) से की जा सकती है।
- जैसे मोबाइल नंबर बदले बिना टेलीकॉम ऑपरेटर बदला जा सकता है, वैसे ही FASTag बदले बिना बैंक बदला जा सकेगा।
- इसके लिए NHAI के 'राजमार्ग यात्रा' मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है।
- पहले बैंक बदलने पर पुराना FASTag बंद कर नया FASTag लेना पड़ता था।
- अब पुराना FASTag स्टिकर हटाने की आवश्यकता नहीं होगी।

गुजरात ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 301 करोड़ रुपये आवंटित किए, आयोजन कंपनी गठित की

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स

10 सितंबर 2026 को गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए 301 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान की जानकारी दी गई। गुजरात को इन खेलों की मेजबानी मिल चुकी है और **Host Collaboration Agreement** पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

◆ 301 करोड़ रुपये का प्रावधान

- कुल प्रावधान — ₹301 करोड़

मुख्य केंद्र — अहमदाबाद, गुजरात

आयोजन — अक्टूबर 2030 में प्रस्तावित

प्रश्न: 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. इन खेलों की मेजबानी गुजरात करेगा।
2. अहमदाबाद को मुख्य आयोजन केंद्र बनाया गया है।
3. आयोजन के लिए गुजरात ने ₹301 करोड़ का प्रावधान किया है।
4. Amdavad 2030 Commonwealth Games Organisation का गठन 12 अगस्त 2026 को किया गया।

कूट:

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1, 2 और 3
- (D) 1, 2, 3 और 4

आगामी ESTIC-2026 (उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन) का आयोजन 27-29 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम दिल्ली में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे; इसमें तीन नोबेल पुरस्कार विजेता और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता वक्ता शामिल होंगे: डॉ. जितेंद्र सिंह

भारत मंडपम में 27 से 29 अक्टूबर 2026 तक दूसरा Emerging Science, Technology, and Innovation Conclave यानी ESTIC 2026 आयोजित किया जाएगा।

थीम

“Creative Minds, Catalyzing Science, Empowering Technologies”

ESTIC 2026 क्या?

- ESTIC का पूरा नाम **Emerging Science, Technology and Innovation Conclave** है।
- यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और नीति-निर्माण को जोड़ने वाला मंच है।
- 2026 इसका दूसरा सम्मेलन है।
- इसका मुख्य उद्देश्य शोध को बाजार-उपयोगी समाधान और व्यवसाय में बदलना तथा भारत की नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

मिशन रंगीन मछली 2031

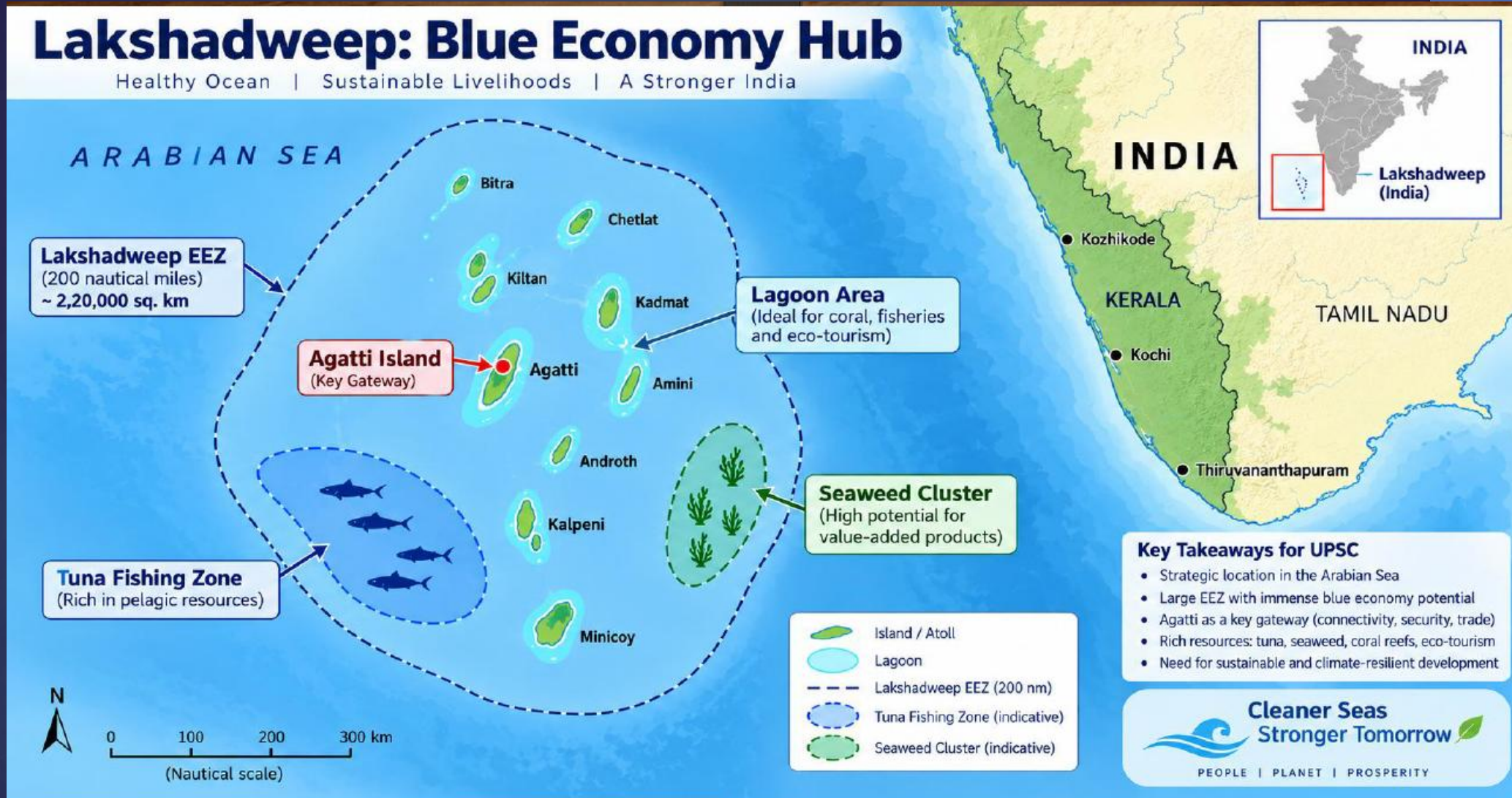
- लॉन्च: 31 अगस्त 2026, अगत्ती (लक्षद्वीप)
- उद्देश्य: सजावटी मत्स्य पालन (Ornamental Fisheries) का विकास।
- मुख्य प्रावधान: पूरी मूल्य शृंखला में वैज्ञानिक प्रबंधन, जैव-सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक अनुपालन के लिए समान ढाँचा व मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs)।

लक्षद्वीप का महत्व

- EEZ: लगभग 4 लाख वर्ग किमी — भारत के कुल EEZ का करीब 17%।
- लैगून क्षेत्र: लगभग 4,200 वर्ग किमी।
- समुद्री शैवाल क्लस्टर: समुद्री शैवाल की खेती एवं मूल्य संवर्धन के लिए समर्पित क्लस्टर।
- टूना हब: विशेष रूप से येलोफिन टूना और स्किपजैक टूना के लिए महत्वपूर्ण।

Lakshadweep: Blue Economy Hub

Healthy Ocean | Sustainable Livelihoods | A Stronger India



● MERCURY'S SHRINKAGE MAY BE 30% GREATER THAN PREVIOUSLY BELIEVED — A LOSS IN DIAMETER OF AS MUCH AS 23 KILOMETERS

Mercury may be shrinking much faster than scientists expected

Marcia Dunn

Cape Canaveral, September 10

A NEW study shows that little, wrinkly Mercury may be shrinking faster than expected, the cosmos' version of a grape shriveling into a raisin under the sun.

Scientists from the German Aerospace Center's Institute of Space Research reported Thursday that Mercury's shrinkage may be 30% greater than previously believed — a loss in diameter of as much as 14 miles (23 kilometers).

That's significant for a planet barely 3,000 miles (4,900 kilometers) across.

Mercury's rough surface, continually reshaped by debris hurled from impact craters, may have hidden the true extent of the loss, according to the researchers whose findings appear in the journal *Geophysical Research Letters*.

The news comes one week after a pair of European and Japanese spacecraft shed its cruising platform and advanced toward Mercury.

Known as BepiColombo, the linked craft are expected to enter orbit around Mercury in November before splitting up for a fuller survey.

BepiColombo's laser instrument should confirm how much Mercury is withering as



Mercury as seen by NASA's Messenger spacecraft during a 2013 flyby.

NASA/JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS LABORATORY VIA AP

a result of internal cooling, said Gaku Nishiyama, the study's lead author who is tak-

ing part in the space mission.

The shrinkage could be even more than his team is es-

timating based on measurements from NASA's Messenger spacecraft in the 2010s.

Only one other spacecraft has ever visited Mercury, NASA's Mariner 10 in the 1970s.

Our solar system's smallest and innermost planet has been shrinking ever since its formation 4.5 billion years ago. Its hot iron core — oversized for such a small world — cools and contracts along with the mantle and crust, tightening the surface like a girdle to fit its new slimmer self.

Nishiyama and his team compared maps showing faults and other geologic signs of contraction at Mercury with

newer maps highlighting surface roughness.

They discovered that the roughest patches exhibited fewer shrinkage wrinkles.

The missing wrinkles could be buried under impact debris, they said.

After accounting for these obscured regions, the researchers provided a fresh take on Mercury's shrinkage that could shed light on other contracting worlds, said Nishiyama, who is affiliated with Hokkaido University in Japan.

"We are quite excited," Nishiyama said in an email, adding that it feels like "we are approaching the reality of Mercury's evolution." AP

बुध ग्रह (Mercury) के सिकुड़ने की नई खोज

- एक नए अध्ययन के अनुसार बुध ग्रह पहले के अनुमान से लगभग 30% अधिक सिकुड़ रहा है। इसके व्यास में अब तक अनुमानित कमी लगभग 23 किमी तक हो सकती है।
- बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है।
- इसका व्यास लगभग 4,900 किमी है।
- बुध के अंदर स्थित गर्म लौह कोर (Iron Core) धीरे-धीरे ठंडा होकर सिकुड़ रहा है।
- कोर के सिकुड़ने से मेंटल और क्रस्ट भी सिकुड़ते हैं, जिससे सतह पर **Wrinkles/Geological Faults** बनते हैं।

Fresh Green Card hurdle: What's the PERM system targeted by US

Soumyarendra Barik
New Delhi, September 10

THE US Department of Labor on September 8 suspended IT services giant Cognizant's filings under PERM, a key system used by American employers to sponsor foreign workers for permanent residency, as authorities investigate alleged fraud and misuse of employment-based immigration programmes. Similar action was announced against software company Cloud-era. US authorities have not yet disclosed the specific allegations against Cognizant, the number of applications affected or the duration of the suspension.

The action comes amid a broader crack-down by the Donald Trump administration on employment-based immigration, with technology and IT services companies facing scrutiny over reliance on foreign workers.

US authorities have stepped up investigations into claims of wage undercutting, fraudulent filings and displacement of American workers. The scrutiny is significant for Indian professionals, who account

for a large share of H-1B beneficiaries and employment-based Green Card applicants.

What is PERM?

PERM, or Program Electronic Review Management, is the system through which employers obtain labour certification before sponsoring a foreign employee for an employment-based Green Card. Unlike a visa application, which is primarily made by an individual, the PERM filing is done by the employer on behalf of the worker.

Before filing, an employer must obtain a prevailing wage determination for the position and carry out prescribed recruitment. Broadly, the process is intended to establish that hiring a foreign worker permanently will not adversely affect the job opportunities, wages or working conditions of US workers. Once the Labour Department certifies the application, the employer can proceed to the next stage of the Green Card process. The date on which the Labour Department accepts the labour certification application also generally becomes the worker's "priority date", which is effectively

Cognizant under lens

- US-headquartered Cognizant had 3,56,700 employees globally as of June 2026. At 2025-end, over 2,50,000 of its employees were based in India.

- This does not mean all of them are affected by the US action. But Cognizant's large Indian employee base and its longstanding use of US employment-based immigration routes mean Indians are likely to make up a significant share of those affected.

their place in the queue for an employment-based immigrant visa.

How is it different from H-1B?

An H-1B is a temporary, non-immigrant work visa that allows US employers to employ foreign professionals in speciality occupations. PERM, in contrast, is part of the process to obtain permanent residency.

The two can, therefore, run alongside. An Indian, for instance, could be working for Cognizant in the US on an H-1B visa while the company separately files a PERM application to sponsor the employee for a Green Card. A PERM suspension, on its own, does not cancel an employee's existing H-1B status or an already-issued Green Card.

How will Indian workers be affected?

For Cognizant employees whose Green Card process has not yet reached the PERM filing stage, the immediate consequence is a delay. Cognizant cannot make fresh PERM filings now, meaning affected employees cannot secure a priority date and begin moving through the employer-spon-

sored Green Card process.

That can be particularly consequential for Indians because they already face a severe backlog. In the US State Department's September 2026 Visa Bulletin, the employment-based second preference, or EB-2, category for India was listed as "unavailable" for final action, while the EB-3 final action date was January 1, 2014. The system also imposes limits on the number of employment-based Green Cards available to nationals of any one country.

There can also be an H-1B implication for some workers approaching the normal six-year limit on that visa. US rules allow certain H-1B holders to extend their stay beyond six years where a labour certification was filed sufficiently early. An inability to get the PERM process started could therefore become more serious for employees nearing that deadline. Workers who already have approved petitions and are waiting because a Green Card number is unavailable are in a different position and can, subject to the rules, qualify for H-1B extensions of up to three years at a time.

US का PERM सिस्टम

- अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor) ने 10 सितंबर को IT services company Cognizant की PERM से जुड़ी 8 filings को suspend किया
- PERM क्या है?
- PERM = Program Electronic Review Management
- यह US Department of Labor की प्रक्रिया है।
- अमेरिकी employer द्वारा किसी foreign worker को employment-based Green Card के लिए sponsor करने से पहले इसका उपयोग किया जाता है।

H-1B	PERM
Temporary, non-immigrant work visa	Permanent residency/Green Card process का हिस्सा
US में specialty occupation में काम की अनुमति	Foreign worker को permanent employment के लिए sponsor करने की प्रक्रिया
Temporary status	Permanent residence की दिशा में कदम

Thanks For Watching

Follow us for more Updates



@RRESULTMITRAOFFICIAL



Join our Telegram



@SUNILVERMA_THEIASMENTOR



Follow on Instagram



Subscribe Now

Stay Connected

Learn
Share
Grow
Together ♥

Better
Students
Brighter
Tomorrow

DISCIPLINE
CONSISTENCY
SUCCESS

Small
Steps
Big
Results
😊